

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 67/2011


- 1 जीवणसिंह पुत्र केसरसिंह।
- 2 मोतीसिंह पुत्र केसरसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दादली तहसील व जिला सीकर।

अपीलांत

बनाम

- 1 दयाल सिंह पुत्र बचनसिंह।
- 2 श्रीमती प्रेम कंवर पुत्री बचनसिंह।
- 3 श्रीमती ओमकंवर पुत्री बचनसिंह।
- 4 श्रीमती मैना कंवर पुत्री बचनसिंह।
- 5 श्रीमती चान्द कंवर पुत्री बचनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दादली तहसील व जिला सीकर।
- 6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सीकर।
- 7 भागीरथ सिंह पुत्र केसरसिंह।
- 8 गोलूसिंह उर्फ दुर्जन सिंह पुत्र केसरसिंह (फौत)।
- 8/1 सोन कंवर पत्नी गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह।
- 8/2 सूरजभान सिंह पुत्र गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह।
- 8/3 सरोज कंवर पुत्री गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह।
- 8/4 सुरेन्द्र सिंह पुत्र गोलूसिंह उर्फ दुर्जनसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण दादली तहसील व जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांकित 19.05.2011 न्यायालय  
उपखण्ड अधिकारी सीकर बउनवानी बचनसिंह बनाम  
जीवणसिंह आदि राजस्व वाद संख्या 227/1996 दावा  
बाबत उद्घोषणा स्थाई निषेधाज्ञा व दुरुस्ती इन्द्राजात  
अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी  
अधिनियम।

उपस्थिति :


1. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री बजरंग सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोंडेंट

—निर्णय—

दिनांक:- 16.11.2022 .

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 227/1996 में पारित निर्णय दिनांक 19.05.2011 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता बचनसिंह ने एक दावा अपीलार्थीगण व रेस्पोंडेंट संख्या 7 व 8 एवं उनकी माता श्रीमती चन्द्रबाई के विरुद्ध ग्राम चैनपुरा तहसील व जिला सीकर के अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 298 रकबा 0.80 हैक्टेयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 278 रकबा 3 बीघा 7 बिस्वा थे उक्त भूमि को पैतृक संयुक्त कब्जा काश्त की बताकर दावा पेश किया था जिसमें विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 19.05.2011 को उक्त चुनौतीग्रस्त निर्णय पारित किया जाकर रेस्पोंडेंट संख्या 1 ता 5 के पिता वादी बचनसिंह को 1/2 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की है।

  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी द्वारा विवादित भूमि को पैतृक बताकर 1/2 हिस्से की उद्घोषणा चाही गई थी। विचारण न्यायालय में अपीलांट ने जवाब दावा प्रस्तुत कर विवादित भूमि पैतृक नहीं होकर स्वअर्जित होने का कथन किया है। वादी के पिता की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के पूर्व हो गई थी। विवादित भूमि पैतृक नहीं है। जवाब दावे के विशेष कथन में अंकित किया है कि विवादित भूमि केसर सिंह की स्व अर्जित सम्पदा है। विचारण न्यायालय ने विशेष कथन में अंकित कथनों पर तनकी कायम नहीं की है। विचारण न्यायालय में वादी ने पी.एन.बी. बैंक को पक्षकार नहीं बनाया है जबकि विवादित भूमि बैंक के रहन थी। विचारण न्यायालय में स्वतंत्र गवाह उपस्थित नहीं हुआ है। विचारण न्यायालय ने आदेश 20 नियम 5 की पालना किये बिना प्रतिकुल कब्जे के आधार पर निर्णय पारित कर विधिक भूल की है। खसरा गिरदावरी के आधार पर खातेदारी प्रदान नहीं की जा सकती है। विचारण न्यायालय के समक्ष लगान अदा करने का कोई उल्लेख नहीं आया है। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय में साक्ष्य का विवेचन किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 1997 पेज 606, आर.एल.डब्ल्यू 2007(2) पेज 1040, आर.आर.डी. 1993 पेज 124, आर.आर.डी. 2019 पेज 148, आर.आर.डी. 1998 पेज 44 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में झुंझजी के पुत्र बचनसिंह द्वारा ग्राम चैनपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 298,278 में पैतृक भूमि होने के आधार पर 1/2 हिस्से की खातेदारी का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट ने प्रदर्श 4 खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2033 प्रस्तुत की है। इस

भू-प्रबंध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर

गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 प्रविष्टियों सहित खातेदार/गैर खातेदार का नाम में केसर सिंह व बचनसिंह पिसरान झुंझजी जाति राजपूत साकिन दादली हिस्सा बराबर का अंकन है। विवादित भूमि केसर सिंह को जागिरदार से प्राप्त हुई हो, धारा 19 में खातेदारी प्राप्त हुई हो ऐसा कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श 4 के खातेदारी एवं काश्तकारी के अंकन से विवादित भूमि पैतृक होना एवं विवादित भूमि में वादी का 1/2 हक हिस्सा होना एवं कब्जा काश्त होना भलीभांति साबित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार कर डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

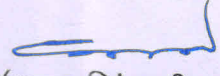
हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में झुंझजी के पुत्र बचनसिंह द्वारा ग्राम चैनपुरा तहसील व जिला सीकर की भूमि खसरा नम्बर 298,278 में पैतृक भूमि होने के आधार पर 1/2 हिस्से की खातेदारी का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने प्रतिवादीगण के जवाब दावे के आधार पर तनकीयात कायम की गई है। विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोंडेंट ने प्रदर्श 4 खसरा गिरदावरी संवत् 2011 से 2033 प्रस्तुत की है। इस गिरदावरी के कॉलम संख्या 5 प्रविष्टियों सहित खातेदार/गैर खातेदार का नाम में केसर सिंह व बचनसिंह पिसरान झुंझजी जाति राजपूत साकिन दादली हिस्सा बराबर का अंकन है। विवादित भूमि केसर सिंह को जागिरदार से प्राप्त हुई हो, धारा 19 में खातेदारी प्राप्त हुई हो ऐसा कोई साक्ष्य विचारण न्यायालय अथवा अपील न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। विचारण न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श 4 के खातेदारी एवं काश्तकारी के अंकन से विवादित भूमि पैतृक होना एवं विवादित भूमि में वादी का 1/2 हक हिस्सा होना एवं कब्जा काश्त होना भलीभांति साबित है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने वाद वादी स्वीकार कर डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि

भूजबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर

नहीं की है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का विवेचन कर विधि सम्मत रूप से विचाराधीन निर्णय व डिक्री पारित किया है। इसमें हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते हैं। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
(धारा 133(1) सी.आर.ए.)  
पदेन राजस्व अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,  
सीकर